पत्रकारों के लिए आचार संहिता

3048. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता विकसित/निर्मित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् ने अब तक क्या-क्या पहल की है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप, उक्त संहिता की कोई रूप-रेखा तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आचार संहिता की मुख्य रूप-रेखा क्या है और यदि वह अब तक तयार नहीं हुई है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) से (ग) भारतीय प्रस परिषद् को कानून के अंतर्गत उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने का कार्य सौंपा हुआ है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिषद् में भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से पूर्व परिषद् (1966—75 के बीच) और मौजूदा परिषद् (1979—82 और 1982—84 के बीच) के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर न्याय-निर्णयों और उनसे विकसित सिद्धांतों का संग्रह तैयार किया है ताकि वह प्रेस कर्मियों के आचरण के लिए मार्गदर्शन का काम कर सके। इस संग्रह का "वायलेशन आफ जर्नलिस्टिक इथिक्स एण्ड पब्लिक टेस्ट" नामक पहला भाग समाचारपत्रों/एजेंसियों/पत्रकारों के विरुद्ध परिषद् द्वारा दिए गए विभिन्न न्याय-निर्णयों से संबंधित है। इस पुस्तक को 6 विभिन्न भागों अर्थात् (1) साम्प्रदायिक लेखन, (2) जवाब देने का अधिकार, (3) समाचारों को सत्यापित न करना, (4) अपमानजनक और अश्लील लेखन, (5) अश्लील और भट्टी रुचि, और (6) पत्रकारिता अनौचित्य में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक में एक शीर्षक विशेष के अंतर्गत परिषद् द्वारा 1966—75 और 1979—82 के बीच दिए गए निर्णयों के कतिपय सेट और अंत में न्याय-निर्णयों में अंतर्निहित मोटे सिद्धांत और उनसे निकले निष्कर्ष दिए हुए हैं।

पूंजी निवेश की दर में गिरावट

3049. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूंजी निवेश की दर में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) नई परियोजनाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाए जाने की मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है, जो कि 1983-84 में 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 24.4 प्रतिशत हो गई और 1985-86 में यह और बढ़कर 24.6 प्रतिशत हो गई। सीमा शुल्कों का निर्धारण, परियोजनाओं की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव और स्वदेशी उत्पादन के संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपना कर किया जाता है।

शेयरों पर ओवर ड्राफ्ट प्राप्त करने की सीमा बढ़ाए जाने की मांग

3050. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने अपने शेयरों पर ओवर-ड्राफ्ट प्राप्त करने की सीमा को बढ़ाये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजव बैंक ने सूचित किया है कि उसे पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से शयरों के बदले ओवर ड्राफ्टों की सीमाएं बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

स्विस बैंकों में जमा धनराशि

3051. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रिजव बैंक की अनुमति से कितनी भारतीय फर्मों/व्यक्तियों ने स्विस बैंक खातों में धनराशि जमा करा रखी है, और उनके द्वारा अलग-अलग कितनी राशि जमा कराई गई है ;

(ख) भारतीयों द्वारा वहां अवैध रूप से जमा कराई गई कुल धनराशि की तुलना में इस राशि का प्रतिशत कितना है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी फर्मों/व्यक्तियों के अवैध खातों के वहां होने का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में अवैध रूप से जमा कराई गई कुल राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह प्रतिशत निकालना संभव नहीं है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय ने स्विटजरलैण्ड में अवैध रूप से रखे गए 9 बैंक खातों का पता लगाया है।

Outstanding Bank Credits

3052. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the state-wise bank credits both central and state outstanding at present;

(b) what is the breakup State-wise, number of beneficiaries who have drawn below Rs. 5000/- between Rs. 5001-10,000, between 10,001-20,000 and 20,001-50,000. 50,001-100,000 and 1 lakh and above;

(c) what is the extent of defaults in the above categories; and

(d) what is the distribution of credits for various priority items, statewise and whether any revisions are proposed to encourage rural agricultural sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Statewise advances of public sector banks as at the end of December 1986 are set out in the Statement. (*See* below)

(b) and (c) Reserve Bank of India has reported that data reporting system of banks does not yield information in the manner asked for.

(d) State-wise advances to priority sector by public sector banks are available for period ending December, 1985 and are set out in the Annexe. As per Reserve Bank of India's guidelines Banks are to ensure that their share of Director Agricultural Advances in total advances is atleast 16 per cent after March, 1987.